



AGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED

(Formerly known as Devki Leasing and Finance Limited)

CIN: L74110RJ1993PLC085542

Date: 24.04.2026

To,
The Manager, Listing Department
Bombay Stock Exchange Limited (BSE)
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort
Mumbai- 400001.

SCRIPT CODE- 530765. SCRIP NAME: AGARWAL

Subject: Newspaper Advertisement regarding opening of Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares.

Dear Sir/Madam,

Pursuant to SEBI circular no. HO/38/13/11(2)2026-MIRSD-POD/I/3750/2026 dated 30/01/2026 dated 2nd July, 2025 and Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find attached herewith copies of the advertisement published in Financial Express (English Edition) and Nafa Nuksan (Hindi Edition) on 24.04.2026, intimating shareholders regarding opening of Special Window for re-lodgement of transfer requests of physical shares.

You are requested to kindly take the above on your records.

Thanking You,
Yours faithfully,

For AGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED

Aditi Parmar
(Company Secretary & Compliance Officer)
Membership No.- A37301

(Representatives are evaluated at: _____)

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal, New Delhi, Bench-VI, has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of M/s OM KRISHNA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED on 22/04/2026.

The creditors of M/s OM KRISHNA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 06th May, 2026 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

A financial creditor belonging to a class, as listed against the entry No. 12, shall indicate its choice of authorised representative from among the three insolvency professionals listed against entry No. 13 to act as authorised representative of the class (Real Estate Allottee) in Form CA.

The submission of claims to be made in accordance with Chapter III of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016. The claim with proofs to be submitted in following specified forms along with documentary proof in support of claim:

Form B: Claim by operational creditors except workmen and employees

Form C: Claim by financial creditors

Form CA: Claim by financial creditors in a class

Form D: Claim by workmen or an employee

Form E: Claim submitted by an authorised representative of workmen or employees

Form F: Claim by creditors (other than financial creditors or operational creditors)

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of the Interim Resolution Professional
Viender Sharma
Interim Resolution Professional-
M/s. OM KRISHNA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
IP Registration No. - IBBI/PA-003IP-N060005/2016-2017/100022
Address: IRSA Insolvency Professionals LLP
11 (3rd floor) Hargovind Enclave, Vikas Marg, Delhi- 110092
E-Mail-ID: viender@vsa.net.in

Date: 24.04.2026
Place: Delhi
Process e-mail id: okd.cprl@gmail.com
AFA Valid upto 31.12.2026

For Your Information

Number of
demat accounts
in India by FY
(In Million):



2025: 185

2023: 114

2022: 90

2021:55:00

2020:41:00

2019:36:00

2018:32:00

2017:28:00

2016:25:00

2015:23:00

2014:22:00

(RBI, Goldman Sachs, Motilal
Oswal & Company data)

Compiled by Nafanuksan Research

अमृत वचन



मां ने अंगुली एकड़कर वलना
सिखाया है तो पिता ने कंधे पर
बिनाकर आगे बढ़ने के
साथने दिखाये हैं। मां के दूध और
पिता के पल्लोने को कभी बुझाश्रम
में लाकन न होने दें।

- श्री कृष्णदा

Thoughts of the time

Faddists are continually
proclaiming the value of
exercise. Four people out of
five are more in need of rest
than exercise.

- Logan Clendenning

The more you sweat in
peacetime, the less you bleed
during war.

- Suresh Rathi

राजस्थानी कहावत

घणौ लड़े सो सूरमौ नौ बाजें

अधिक लड़े वह शूरवीर

नही कहलाता

■ हरदम किसी से लड़ते रहना वीरता
की बजाय बुवाई का ही लक्षण है।

-रव. विजय दान देवा

साधार : रूपारण संस्थाएं, बोकईदा

एफडीआई वाली कंपनियों की नेट सेल्स ग्रोथ 2024- 25 में घटकर रही 8.7%

मुंबई@एजेंसी। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) वाली कंपनियों की शुद्ध विक्री वृद्धि वर्ष 2024-25 में घटकर 8.7 प्रतिशत रह गई, जो इससे पिछले वर्ष 9.4 प्रतिशत थी। इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली। केंद्रीय बैंक ने भारत में गैर-सरकारी गैर-वित्तीय (एनजीएनएफ) प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित आंकड़े जारी किए। ये आंकड़े 3,100 कंपनियों के ऑडिट किए गए वार्षिक खातों पर आधारित हैं, जिन्होंने भारतीय लेखा मानक प्रारूप में अपनी रिपोर्ट दी थी।

आरबीआई ने कहा, उद्योग के आधार पर देखें तो सेवा क्षेत्र की शुद्ध विक्री वृद्धि पिछले वर्ष के 12.2 प्रतिशत से मामूली बढ़कर 12.7 प्रतिशत हो गई, जबकि विनिर्माण क्षेत्र के लिए यह पिछले वर्ष के 6.8 प्रतिशत से घटकर 5.1 प्रतिशत रह गई। इन आंकड़ों में शामिल कंपनियों में आधी से अधिक कंपनियों में सिंगापुर, अमेरिका और मॉरीशस से प्रत्यक्ष निवेश था। भारत में प्रत्यक्ष निवेश के अन्य प्रमुख स्रोतों में जापान, नीदरलैंड और ब्रिटेन शामिल थे। इसमें कहा गया है कि आंकड़ों में शामिल अधिकांश कंपनियाँ विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की थीं। सेवा क्षेत्र के भीतर एक-तिहाई से अधिक कंपनियाँ सूचना और संचार उद्योगों से संबंधित हैं। बिक्री में मामूली वृद्धि और बढ़ते खर्चों के बीच परिचालन लाभ की वृद्धि 2024-25 में घटकर 10.7 प्रतिशत रह गई, जो इससे पिछले वर्ष 22.1 प्रतिशत थी। पब्लिक लिमिटेड एफडीआई कंपनियों की तुलना में प्राइवेट लिमिटेड एफडीआई कंपनियों ने अधिक लाभ वृद्धि दिखाई।

जनवरी-मार्च 2026 क्वार्टर : संगम इंडिया ने रिपोर्ट किये रिकॉर्ड रेवेन्यू व प्रॉफिट

जयपुर@कॉ.सं। भीलवाड़ा की प्रमुख टेक्सटाइल कंपनी संगम (इंडिया) लिमिटेड, जो कि सिंथेटिक ब्लैंडेड, कॉटन और टेक्सचराइज्ड यार्न, फैब्रिक्स, डेनिम फैब्रिक्स और रेडीमेड सीमलेस कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग व बिक्री के कारोबार में एक्टिव है, ने हाल ही में जनवरी-मार्च 2026 क्वार्टर एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने वित्तीय परिणामों की घोषणा की है। इस दौरान कंपनी का सॉलिड परफॉर्मेंस दर्ज किया गया है। जनवरी-मार्च 2026 क्वार्टर में कंपनी की कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 19.44 फीसदी बढ़कर 866 करोड़ रुपए दर्ज की गई, जो पिछली समान अवधि में 725 करोड़ रुपए थी। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 277 फीसदी बढ़कर 9 करोड़ रुपए के मुकाबले 34 करोड़ रुपए हो गया। संगम इंडिया ने जनवरी-अप्रैल 2026 क्वार्टर में अपने इतिहास के सर्वाधिक क्वार्टरली रेवेन्यू व नेट प्रॉफिट अर्जित किये हैं। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 53 करोड़ रुपए से बढ़कर 99 करोड़ रुपए हो गया। साथ ही कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 7 फीसदी से बढ़कर 11 फीसदी हो गया। हालांकि कंपनी की इंस्ट्रेस्ट कॉस्ट 24 करोड़ रुपए से बढ़कर 26 करोड़ रुपए दर्ज की गई।

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी की

यह ग्रोथ अच्छे ऑर्डर्स, बढ़ती
डिमांड और एक्सपोर्ट बिजनेस
की वजह से



कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 12.20 फीसदी बढ़कर 3190 करोड़ रुपए दर्ज की गई, जो पिछली समान अवधि में 2843 करोड़ रुपए थी। इस दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 218 फीसदी बढ़कर 27 करोड़ रुपए के मुकाबले 86 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 225 करोड़ रुपए के मुकाबले बढ़कर 311 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 8 फीसदी के मुकाबले 10 फीसदी दर्ज किया गया। यह ग्रोथ अच्छे ऑर्डर्स, बढ़ती डिमांड और एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ने की वजह से आई है। कंपनी का मार्जिन भी स्ट्रॉन बना हुआ है, यानी सेल्स से अच्छा प्रॉफिट मिल

रहा है। कंपनी अब ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट्स बना रही है जिनमें ज्यादा मार्जिन मिलता है, जिससे उसकी ओवरऑल आर्निंग बेहतर हो रही है। कंपनी का एक्सपोर्ट भी बढ़कर लगभग 1,167 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में कंपनी की रेवेन्यू रिकॉर्ड लेवल पर दर्ज की गई है। कंपनी के पास करीब 195 करोड़ रुपए का कैश भी है, जिससे वह आने वाले समय में नए प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन कर सकती है। आगे के लिए कंपनी की स्ट्रेटेजी है कि वह अपने प्रोडक्ट्स को और बेहतर बनाएगी और एक्सपोर्ट पर फोकस बढ़ाने के साथ और रिन्यूएबल एनर्जी (जैसे सोलर और विंड) का ज्यादा इस्तेमाल करेगी। कंपनी का शेयर गुरुवार को बीएसई पर 1.5 फीसदी गिरावट के साथ 530 रुपए पर बंद हुआ। पिछले एक माह के दौरान कंपनी के शेयरों में करीब 25 फीसदी से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की जा चुकी है।

संगम इंडिया लि. के सीएफओ सीए.आर.दाखरा के मुताबिक कंपनी का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 95 फीसदी पर चल रहा है। ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट अच्छे होने के कारण डिमांड अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी का स्टॉक मिनिमम लेवल पर चल रहा है। यह ग्रोथ आगे भी सस्टेन करेगी।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना : तीस हजार युवाओं को ब्याज मुक्त लोन दिलवायेगी राज्य सरकार

जयपुर@का.सं। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत 30,000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य को क्रियान्वित करने की तैयारी चल रही है। इंडस्ट्री एंड कॉमर्स विभाग ने लोन वितरण में तेजी लाने के लिए लक्ष्य से दोगुना यानी 60,000 एप्लीकेशन जून माह तक बैंकों को भेजने की योजना बनाई है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इनमें से 30,000 आवेदन अप्रैल माह के अंत तक, उसके बाद मई और जून में 15,000-15,000 आवेदन भेजे जाएंगे।

इस योजना के तहत, कक्षा 8 से 12 पास आवेदक सेवा और व्यापार के लिए 3.5 लाख रुपये और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 7.5 लाख रुपये तक के इंस्ट्रेस्ट फ्री लोन के पात्र हैं। उन्हें 35,000 रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता भी मिलेगी। स्नातकों, आईटीआई ट्रेड एप्लीकेंट और हाई एजुकेशन प्राप्त लोगों के लिए सर्विस और ट्रेड सेक्टर के लिए 5 लाख रुपये तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए

10 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करती है, साथ ही 50,000 रुपये तक की मार्जिन मनी सहायता भी देती है। जिलों को निर्धारित टाइम लाइन में अपने निर्धारित लक्ष्यों से दोगुनी संख्या में आवेदन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उद्योग और वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि इस स्कीम के तहत अब तक 73,000 से ज्यादा एप्लीकेशन मिल चुकी हैं। ये आवेदन उन लोगों की तरफ से आए हैं, जो अपना खुद का कारोबार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद चाहते हैं। इन आवेदनों से कुल मिलाकर लगभग 3,580 करोड़ रुपये के लोन की मांग सामने आई है। अब तक जिला उद्योग केंद्रों द्वारा 31,000 से ज्यादा आवेदन बैंकों को भेजे जा चुके हैं। इस योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 12 जनवरी, 2026 को की थी, और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 22 जनवरी से शुरू हुई। सक्सेना ने कहा कि सरकार का लक्ष्य बड़ी संख्या में युवाओं को आर्थिक सहायता देकर स्वरोजगार का माहौल तैयार करना है।

नेशनल ● इंटरनेशनल

‘इंडिया बिना सुधारों के आत्मसंतोष का जोखिम उठाता है’

नयी दिल्ली@एजेंसी

ब्रोकरेज कंपनी बर्नस्टीन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नाम लिखे एक खुले पत्र में आगाह किया कि यदि भारत संरचनात्मक सुधारों, विशेषकर रोजगार, विनिर्माण एवं नवाचार में तेजी नहीं लाता है तो हाल के आर्थिक लाभ व्यर्थ हो सकते हैं।

इसमें कहा गया है, “पिछले छह वर्ष दिखाते हैं कि जब नीतियाँ समन्वित होती हैं तो भारत क्या कर सकता है। लेकिन समय ही एक जोखिम भी है.... यह मान लेना कि हाल की सफलता आगे भी जारी रहेगी और इस बात को कम आँकना कि अभी कितना काम बाकी है।”

पत्र में पूंजीगत व्यय की ओर झुकाव से प्रेरित मजबूत वृहद स्फिरता और आय वृद्धि का उल्लेख किया गया। बर्नस्टीन ने कहा कि वैश्विक जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) रैंकिंग में भारत की बढ़त और सफ़िडी के बजाय बुनियादी ढांचे पर ध्यान ने वृद्धि को आधार दिया है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य तेजी से बदल रहा है जहाँ आपूर्ति श्रृंखलाएँ पुनर्गठित हो रही हैं और प्रौद्योगिकी व्यवधान तेज हो रहा है। एक प्रमुख चिंता रोजगार है, खासकर तब जब ‘जनरेटिव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस’ (जेन एआई) उस सेवा क्षेत्र के लिए खतरा बन रहा है जिसने दशकों तक भारत के मध्यम वर्ग को आगे बढ़ाया है। बर्नस्टीन ने साथ ही यह भी सवाल उठाया कि क्या विनिर्माण क्षेत्र बड़े पैमाने पर विस्थापित श्रम को समायोजित कर सकता है। यह देखते हुए कि निजी पूंजीगत व्यय चयनात्मक बना हुआ है और बहुचर्चित “चीन+1” बदलाव को रोजगार में तब्दील होने में समय लग रहा है। पत्र में कहा गया है, “अंततः, कोई देश अपने लोगों को कहाँ और कैसे तैनात करता है, यही उसके दीर्घकालिक भविष्य को निर्धारित करता है।”

इसमें कहा गया, “क्या हमारी वृद्धि गाथा का अगला चरण अधिक इंजीनियर, उत्पाद निमाताओं और नवप्रवर्तकों का सृजन करेगा, या यह मुख्य रूप से अधिक चालकों, डिजिटली कर्मचारियों और घरेलू सहायकों का सृजन करेगा?”

संरचनात्मक बाधाएँ : पत्र में कृषि को एक प्रमुख बाधा बताया गया, जहाँ लगभग 42-45 प्रतिशत कार्यबल केवल 15-16 प्रतिशत जीडीपी में योगदान देता है। इसमें कृषि कानूनों की वापसी के बावजूद सुधारों को फिर से शुरू करने, सिंचाई

बढ़ाने और सफ़िडी पर निर्भरता कम करने की बात कही गई। ऊर्जा के क्षेत्र में, ब्रोकरेज कंपनी ने बिजली वितरण में लगातार अक्षमताओं और आयातित कच्चे तेल पर भारी निर्भरता (जो लगभग 88 प्रतिशत मांग पूरी करता है) की ओर इशारा किया। इसमें आंतरिक दहन इंजन वाहनों से चरणबद्ध रूप से हटने सहित इलेक्ट्रिक परिवहन की ओर स्पष्ट बदलाव का आह्वान किया गया।

एआई एवं विनिर्माण में दूरी : बर्नस्टीन ने आगाह किया कि भारत बुनियादी प्रौद्योगिकी विकसित करने के बजाय डेटा सेंटर पर ध्यान केंद्रित करके कृत्रिम मेधा (एआई) में पीछे रह सकता है। पत्र में कहा गया,

“यदि भारतीय डेटा का उपयोग वैश्विक मॉडल को प्रतिस्पर्धित करने में होता रहा और घरेलू क्षमता का निर्माण नहीं हुआ, तो भारत एआई अर्थव्यवस्था में स्थायी उपभोक्ता बन सकता है।”

वहीं, नीतिगत पहलों के बावजूद विनिर्माण जीडीपी का लगभग 16-17 प्रतिशत ही बना हुआ है, आपूर्ति श्रृंखलाएँ सीमित हैं और इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी जैसे क्षेत्रों में इंपोर्ट पर निर्भरता अधिक है।

राजकोषीय संतुलन एवं बुनियादी ढांचा : बर्नस्टीन ने राज्यों

द्वारा बढ़ती नकद हस्तांतरण योजनाओं पर भी चिंता जताई, जिनका वार्षिक व्यय 1.7-2.5 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। इसमें कहा गया है, “निवेश की कमी से जूझ रही उभरती अर्थव्यवस्था के लिए यह वृद्धि हासिल करने का बहुत महंगा तरीका है।” पत्र में आगाह किया गया है कि ऐसा खर्च बुनियादी ढांचे के निवेश को प्रभावित कर सकता है और मुद्रास्फीति के जोखिम बढ़ा सकता है। परिवहन के क्षेत्र में, बर्नस्टीन ने विमानन के बजाय रेल एवं जन परिवहन पर अधिक ध्यान देने की वकालत की।

निर्णायक कार्रवाई की जरूरत : पत्र में कहा गया कि अनुसंधान एवं विकास पर भारत का खर्च, जो जीडीपी का लगभग 0.6-0.7 प्रतिशत है... वैश्विक मानकों से काफी कम है जबकि अपेक्षाकृत उच्च कारोधान के बावजूद सार्वजनिक सेवाएँ पिछड़ी हुई हैं।

बर्नस्टीन ने कहा, “भारत में पूंजी, प्रतिभा या महत्वाकांक्षा की कमी नहीं है। अब आवश्यकता है कि कठिन निर्णयों को टालने के बजाय जल्दी लेने की अधिक स्पष्ट इच्छा दिखाई जाए। कार्रवाई का अवसर अब भी खुला है, लेकिन यह तेजी से कम होता जा रहा है।”

मुंबई अल्ट्रा-रिच लोगों की आबादी में 35.4 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ अपना दबदबा बनाए हुए है। दिल्ली की हिस्सेदारी बढ़कर 22.8 प्रतिशत हो गई है, जबकि चेन्नई और हैदराबाद ने भी पिछले दशक में मजबूत वृद्धि दर्ज की है। वहीं, बेंगलुरु की हिस्सेदारी में मामूली गिरावट आई है। नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि भारत के वैश्व आधार में विस्तार देश के अधिक उद्यमशील और वित्तीय रूप से परिष्कृत अर्थव्यवस्था में परिवर्तन को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटलीकरण, सूचीबद्ध शेयर बाजार, निजी पूंजी और परिवारिक स्वामित्व वाले व्यवसाय इस निरंतर धन सृजन के प्रमुख चालक हैं।

बीफ न्यूज

पासवान से मिले बीकानेर उद्योग संघ के प्रतिनिधि

बीकानेर@नि.सं। बीकानेर जिला उद्योग संघ के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात कर बीकानेर की फूड इंडस्ट्री और कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के विकास एवं विस्तार को लेकर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में उद्योगपति हनुमान झंवर एवं सुनील बलदेवा शामिल रहे। प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री के समक्ष बीकानेर की फूड इंडस्ट्री से जुड़ी प्रमुख समस्याएं भी रखीं। उन्होंने बताया कि शहर में फूड टेस्टिंग लैब की अनुपलब्धता उद्योगों के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। वहीं कृषि आधारित उद्योगों पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क जैसे दोहरे कर का बोझ उद्योगों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को प्रभावित कर रहा है। प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय मंत्री को बीकानेर आने का न्योता देते हुए आग्रह किया कि वे यहां आकर उद्योग और व्यापार जगत से जुड़े लोगों के साथ संवाद करें, जिससे समस्याओं के समाधान और उद्योगों के विस्तार को नई दिशा मिल सके। पासवान ने आश्वासन दिया कि वे शीघ्र ही बीकानेर आकर उद्योग जगत से चर्चा करेंगे।



पृथ्वी दिवस पर पोस्टर का विमोचन

जयपुर@का.सं। एस.एस. जैन सुबोध पी.जी. आटोमोमस कॉलेज की राष्ट्रीय सेवा इकाईयों द्वारा विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पोस्टर का विमोचन कॉलेज की प्राचार्या प्रो. रेणु जोशी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जोशी ने सभी से आग्रह किया कि पृथ्वी हमारा घर है हमें ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी चाहिए। आसपास की जगह को साफ-सुथरा रखें, अनावश्यक बिजली के खर्च को कम करें, पेड़-पौधों का संरक्षण करें एवं ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगायें। हम हमारी भावी पीढ़ियों को तभी समुचित वातावरण दे पाएंगे जब आज हम पृथ्वी को बचाने का हरसंभव प्रयास करेंगे। इस अवसर पर एन.एस.ए. के कार्यक्रम अधिकारी डॉ. पवन शर्मा, डॉ. मुकेश चंद शर्मा, डॉ. विशाल गौतम एवं डॉ. राकेश भाबाई ने भी अपने विचार व्यक्त किए एवं पृथ्वी को संरक्षित करने का संकल्प दोहराया।



आयकर कर्मचारी महासंघ की द्विवार्षिक अधिवेशन स्मारिका का विमोचन

बीकानेर@नि.सं। आयकर कर्मचारी महासंघ, शाखा बीकानेर द्वारा आयोजित 29वें द्विवार्षिक अधिवेशन की स्मारिका का विमोचन रिद्धि सिद्धि भवन, रानी बाजार में किया गया। विमोचन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आयकर अपर निदेशक (अन्वेषण), जोधपुर प्रेरणा चौधरी उपस्थित रहीं। कार्यक्रम में राजस्थान सर्किल के पदाधिकारी राजेन्द्र मोषा (अध्यक्ष), सियाराम स्वामी (महासचिव), अनुज बिश्नोई (वित्त सचिव) तथा हनुमान शर्मा, आईटीओ (मुख्यालय), आईटीजीओ बीकानेर विशेष रूप से मौजूद रहे। आईटीईएफ जोधपुर के पदाधिकारी नारायण बच्छ (संगठन सचिव), अंकुश बिश्नोई (संयुक्त सचिव) एवं विवेश कड़वासरा (शाखा सचिव, बीकानेर) के निर्देशन में कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयकर विभाग के अधिकारी राकेश सोमानी व शीशराम सैनी सहित अन्य अधिकारियों के साथ बीकानेर के गणगण्य चार्टर्ड अकाउंटेंट सुशील शर्मा, डी.के. सोनी, सोहन लाल बैद, के.डी. सेवग तथा शहर के प्रमुख व्यापारियों ने भी उपस्थिति दर्ज कराई।



इन्फोसिस का चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ 20.8% बढ़कर 8,501 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली@एजेंसी। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी इन्फोसिस का वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 20.8 प्रतिशत बढ़कर 8,501 करोड़ रुपये हो गया। बेंगलुरु मुख्यालय वाली कंपनी का वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में मुनाफा 7,033 करोड़ रुपये रहा था। कंपनी की परिचालन आय वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 13.4 प्रतिशत बढ़कर 46,402 करोड़ रुपये हो गई जो एक साल पहले 40,925 करोड़ रुपये थी। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में इन्फोसिस का शुद्ध लाभ 10.20 प्रतिशत बढ़कर 29,440 करोड़ रुपये रहा जो 2024-25 में 26,713 करोड़ रुपये था। वित्त वर्ष 2025-26 में परिचालन आय 9.6 प्रतिशत बढ़कर 1,78,650 करोड़ रुपये हो गई। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इन्फोसिस ने स्थिर मुद्रा आधार पर 1.5 से 3.5 प्रतिशत राजस्व वृद्धि का अनुमान दिया है। इन्फोसिस के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) एवं प्रबंध निदेशक सलील पारेख ने कहा, “हमने वित्त वर्ष 2025-26 में 3.1 प्रतिशत वृद्धि के साथ मजबूत प्रदर्शन किया, जिसमें 14.9 अरब डॉलर के बड़े सौदे शामिल हैं। यह हमारे उद्यम एआई मूल्य प्रस्ताव की मजबूती और बड़े परिवर्तनकारी अवसरों में बाजार हिस्सेदारी बढ़ने को दर्शाते हैं।” उन्होंने कहा, “छक क्षेत्रों में हमारी एआई सेवाओं की सरल एवं मजबूत एणर्जीति बाजार में गति पकड़ रही है, जिसे मजबूत एआई (कृत्रिम मेधा) साझेदारों से और बल मिल रहा है। इससे ग्राहकों को एआई से मूल्य प्राप्त करने में मदद मिल रही है।” वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के अंत में कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या 3,28,594 थी। इन्फोसिस के मुख्य वित्त अधिकारी जयश संघराजका ने कहा कि कंपनी वित्त वर्ष 2026-27 में 20,000 एप कर्मचारियों की भर्ती की योजना बना रही है।

अधिशारी अभियन्ता, जन स्वा.अभि. विभाग, जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय जयपुर			
क्रमांक : अ.अ./जिला खण्ड-11/2026-27/458-73 दिनांक : 17/4/26			
Phone:-0141-21003090		Email:-ee2-jai.phed@rajasthan.gov.in	
निविदा सूचना संख्या 04/2026-27			
राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से जिला ग्रामीण खण्ड II, जयपुर के अधीन विभिन्न जल योजनाओं पर ब्लॉक निष्ठा कार्य पर भेजित के निविदा सूचना संख्या 04/2026-27 का राजस्थान सरकार के उपर्युक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों की ई-प्रोक्च्यूर के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।			
उन सभी निविदाओं से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.dipr.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है। उपरोक्त निविदाओं का प्रकाशन sppr.rajasthan.gov.in निम्नानुसार कर दिया गया है:-			
क्र.सं.	आई.डी. नम्बर	अपलोड की दिनांक	
4.1	UBNPHE2827 WSOB 00467	17-04.2028	
(हिमांशु मील) अधिशारी अभियन्ता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग जिला ग्रामीण खण्ड द्वितीय जयपुर			
DIPR/C/7257/2026			

AGARWAL FORTUNE INDIA LIMITED

CIN: L74110RJ1993PLC085542

Registered Office: Third Floor, F-2264, RIICO Industrial Area, Ramchandrapura, Sitapura Industrial Area, Jaipur-302022 (Rajasthan)

Email Id: alljaipur@gmail.com | Website: www.agarwalfortune.com | Contact: 91-7230043249

NOTICE TO SHAREHOLDERS
Special Window for Re-lodgment of Transfer Requests for Physical Shares
Pursuant to SEBI Circular no. HO38/13/11(2)2026-MRSD-PDD/3750/2026 dated 30/01/2026, the Shareholders of the Company are hereby informed that a special window has been opened by the Company from February 05, 2026 to February 04, 2027 to facilitate re-lodgment of transfer deeds/Share Certificate, etc., for transfer of physical shares. This window is opened only for re-lodging transfer deeds that were submitted for the transfer of physical shares, and were rejected, returned, or not attended to due to deficiencies in the documents, process, or other reasons. Investors who have missed the earlier deadline of March 31, 2021 and January 06, 2026 are encouraged to take advantage of this opportunity. The shares re-lodged for transfer will be processed only in dematerialised form during this period. Eligible Shareholders may submit their transfer requests along with the requisite documents to the Company's Registrar and Transfer Agent (RTA) i.e. BEETAL Financial & Computer Services Pvt Ltd. (Unit: Agarwal Fortune India Limited) at BEETAL HOUSE, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind LSC, New Delhi - 110002.

By Order of the Board
For Agarwal Fortune India Limited
Sd/-
Aditi Parmar (M. No. A37301)
(Company Secretary & Compliance Officer)

Place: Jaipur

Date: 23.04.2026